माननीय जवाहर लाल गुप्ता, *जे.*

धरमबीर और अन्य- *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अन्य - *प्रतिवादी*

सी. डब्ल्यू. जे. 10649 ऑफ़ 1991

18 दिसंबर, 1991

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद *226- हरियाणा* सरकार *के 26 मई, 1972 के* निर्देश- चपरासियों का *चयन-नियुक्ति के लिए अयोग्य पाए गए योग्यता सूची में कुछ उम्मीदवार-विज्ञापित रिक्तियों के क्षेत्र के भीतर आने वाले याचिकाकर्ता-अपनी-अपनी श्रेणियों में पदों पर नियुक्ति की मांग करने वाले याचिकाकर्ता-यह बचाव कि योग्यता सूची छह महीने के लिए मान्य है, 1972 के* निर्देशों *के बाद से यह प्रदान नहीं किया गया है कि बोर्ड द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची केवल 6* महीने *की अवधि के लिए मान्य है-नियुक्ति से इनकार करने के लिए बोर्ड द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है-बोर्ड ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं करने में* सही *नहीं है क्योंकि उसे नियुक्ति से इनकार करने का कोई मनमाना अधिकार नहीं है- मंडमस रिट द्वारा बोर्ड को नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्तियों पर विचार करने का निर्देश जारी किया।*

अभिनिर्णित किया गया है कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं है कि 26 मई, 1972 के निर्देश प्रतिवादी-बोर्ड पर कैसे लागू होते हैं।यह मानते हुए कि ये निर्देश लागू होते हैं, उनके अवलोकन से पता चलता है कि आयोग या बोर्ड से ऐसी सिफारिश प्राप्त होने के 6 महीने के भीतर ऐसी रिक्तियों को आयोग या बोर्ड द्वारा विभाग को भेजी गई सूचियों से भरा जा सकता है।ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है।इन निर्देशों में यह प्रावधान नहीं है कि बोर्ड द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची केवल 6 महीने की अवधि के लिए मान्य है। नतीजतन, विवाद को कायम नहीं रखा जा सकता है।
(पैरा 5)

इसके अलावा यह अभिनिर्णीत किया गया कि आम तौर पर एक व्यक्ति जिसे किसी पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया है, उसे तब तक नियुक्त किया जाना चाहिए जब तक कि संबंधित व्यक्ति को नियुक्त नहीं करने में अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के कुछ कारण नहीं दिखाए जाते हैं।वर्तमान मामले में, लिखित बयान में किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है, जिसके कारण चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं दिया गया था।मेरे विचार में प्राधिकरण को अपनी मर्जी से नियुक्ति से इनकार करने का आत्यन्तिक या मनमाना अधिकार नहीं है।एक उम्मीदवार जिसने पद के लिए प्रतिस्पर्धा की है

और उपयुक्त पाया जाता है वह एक उचित आशा का हकदार है कि उसे नियुक्त किया जाएगा।इस आशा को केवल एक वैध कारण से ही विफल किया जा सकता है।वर्तमान मामले में कोई वैध कारण नहीं दिखाए जाने के कारण, मुझे प्रतिवादी की ओर से उठाई गई आपत्ति में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

(पैरा 6)

एस. एन. सिंगला, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय तंगरी *के साथ।*

प्रतिवादी की ओर से *एस. के. सूद, अधिवक्ता*

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, जे. (मौखिक)

(1) तीन याचिकाकर्ता की चपरासियों के पदों के लिए सिफ़ारिश की गई जिसका विज्ञापन हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (इसके बाद बोर्ड के रूप में संदर्भित) द्वारा निकाला गया।चयन के बावजूद नियुक्ति प्राप्त करने में विफल रहने के कारण, उन्होंने वर्तमान रिट याचिका द्वारा इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित बयान में यह भी कहा गया है *कि* बोर्ड द्वारा विज्ञापित 52 पदों में से 24 पदों को सामान्य श्रेणी के सदस्यों में से भरा जाना था।इसके अलावा, 19 पद पूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों के लिए, 7 पद पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए और 2 पद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए थे।यह आगे स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 सामान्य श्रेणी से संबंधित है और प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 27 पर रखा गया था।जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 का संबंध है, उनके दावों पर पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए विचार किया गया था।उन्हें इस श्रेणी की योग्यता सूची में क्रम संख्या 23 और 24 पर रखा गया था।यह भी टाल दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि उनके नाम सामान्य श्रेणी के पहले 24 पदों और पूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए 19 पदों में नहीं थे।यह भी कहा गया है कि चयन सूचियाँ केवल छह महीने की अवधि के लिए मान्य हैं, और अवधि समाप्त होने के बाद, याचिकाकर्ताओं को नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है।

(2) याचिकाकर्ताओं की ओर से एक प्रतिकृति दायर की गई है।यह अन्य बातों के *साथ-साथ* अनुमान लगाया गया है कि क्रम संख्या 16,21,22,23 और 24 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए योग्यता सूची में अयोग्य पाए गए हैं। यदि इन 5 व्यक्तियों के नाम योग्यता सूची से बाहर कर दिए जाते हैं, तो याचिकाकर्ता संख्या-1 योग्यता सूची में पहले

24 के भीतर होगा। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 के संबंध में, जो भूतपूर्व सैनिकों के वार्डों के लिए आरक्षित पदों के लिए उम्मीदवार हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न अन्य लोगों के अलावा 3 या 4 व्यक्तियोग्य नहीं पाये गये है। इस परिसर में यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता अपनी श्रेणी के लिए विज्ञापित पदों की संख्या के भीतर हैं।

(3) प्रतिवादी की ओर से एक प्रत्युत्तर दायर किया गया। यह उल्लेख किया गया है *कि* क्रम संख्या 16 में उम्मीदवार को वास्तव में नियुक्त किया गया है।जहाँ तक उम्मीदवारों की योग्यता सूची में क्रम संख्या 21,23 और 24 का संबंध है, प्रतिकृति में कथन को स्वीकार किया गया है।, यह भी कहा गया है कि केवल चयन से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता है और 4 जनवरी, 1990 की योग्यता सूची एक वर्ष की अवधि के लिए वैध थी जो तब से समाप्त हो गई है।यह आगे कहा गया है कि क्रम संख्या 20, 25 और 26 पर उम्मीदवार को नियुक्ति का प्रस्ताव भी नहीं दिया गया है।तदनुसार, यह दावा किया जाता है कि याचिकाकर्ता को नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है।इसी तरह, पूर्व सैनिकों की श्रेणी के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि 24 उम्मीदवारों की सूची में याचिकाकर्ताओं के नाम क्रमिक रूप से संख्या 23 और 24 दिखाई देते हैं। यह भी बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों को याचिकाकर्ताओं से ऊपर रखा गया है, उन्हें अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं।

(4) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश श्री सिंगला ने तर्क दिया है कि जिन पदों का विज्ञापन किया गया है और याचिकाकर्ताओं का विधिवत चयन किया गया है, उन्हें नियुक्त होने का अधिकार है।वकील का तर्क है कि इस अधिकार को केवल कुछ कानूनी और वैध आधारों के लिए पराजित किया जा सकता है।चूंकि लिखित बयान में कोई वैध आधार प्रकट नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को नियुक्त नहीं करने में प्रतिवादी की कार्रवाई पूरी तरह से मनमाना और अवैध है। प्रतिवादी की ओर से, श्री सूद ने तर्क दिया है कि बोर्ड द्वारा तैयार की गई सूची केवल 6 महीने की अवधि के लिए वैध थी, और अवधि समाप्त होने पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं से ऊपर के व्यक्ति जिन्हें नियुक्त नहीं किया गया है, याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकते हैं कि बोर्ड की कार्रवाई या तो अवैध है या मनमाना है। याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 के संबंध में, यह आगे तर्क दिया गया है कि भले ही अयोग्य पाए गए व्यक्तियों की संख्या को बाहर रखा गया हो, याचिकाकर्ता पहले 19 व्यक्तियों में नहीं आते हैं। नतीजतन, उन्हें नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है।

(5) जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 1 का संबंध है, उसे योग्यता सूची में क्रम संख्या 27 पर रखा गया था। यह और स्पष्ट है कि 4 व्यक्ति जिनके नाम योग्यता सूची में क्रम संख्या 21 से 24 में दिखाई देते हैं, बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए गए थे। इस स्थिति में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता संख्या 1

योग्यता में क्रम संख्या 23 पर होगा। सामान्य श्रेणी के लिए पदों की कुल संख्या 24 है, याचिकाकर्ताओं को, सामान्य घटनाओं में, नियुक्ति को हटा दिया जाना चाहिए था।इसलिए श्रेणी के सदस्यों या पूर्व सैनिकों या अन्य आश्रितों के संबंध में, याचिकाकर्ताओं की ओर से किया गया कथन यह है कि बोर्ड द्वारा चुने गए उम्मीदवारों में से 3 या 4 उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं पाए गए हैं।स्पष्ट चित्रण भी दिए गए हैं, जिसमें बोर्ड ने मौन बनाए रखने का फैसला किया है। प्रतिकृति के जवाब में, स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। हालाँकि, इस पहलू पर पक्षों की दलीलें आत्यन्तिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं।प्रतिवादी की ओर से पेश श्री सूद स्पष्ट रूप से यह नहीं बता पाए कि पूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए आरक्षित सभी 19 पदों को भरा गया है या नहीं। इस स्थिति में, यह निर्देश देना उचित है कि बोर्ड सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ-साथ पूर्व सैनिकों

की श्रेणी के उम्मीदवारों को योग्यता के सख्त आदेश में 4 नवंबर, 1989 को विज्ञापित रिक्तियों के खिलाफ नियुक्तियों की पेशकश करेगा।जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 1 का संबंध है, उसे पहले 24 के भीतर होने के कारण तुरंत नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा। यदि उसके खिलाफ कुछ और नहीं है, तो उसे इस पद पर नियुक्त किया जाएगा।इसी तरह, पूर्व सैनिकों के मामले में, योग्यता के आदेश में उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा, और यदि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 से ऊपर कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता है, यदि कोई है, तो याचिकाकर्ताओं को उनके अन्यथा उपयुक्त होने के अधीन नियुक्त किया जाएगा। यह इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर किया जाएगा।

(6) निर्णय से अलग होने से पहले, श्री सूद (एस. आई. सी. प्रतिवादी) की ओर से उठाए गए इस तर्क पर ध्यान दिया जा सकता है कि सूची केवल 6 महीने की अवधि के लिए मान्य है, इस प्रस्तुति के समर्थन में, श्री सूद ने 26 मई, 1972 को मुख्य सचिव द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजे गए एक *पत्र पर* भरोसा किया है। प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट नहीं है कि ये निर्देश प्रतिवादी-बोर्ड पर कैसे लागू होते हैं।यह मानते हुए कि ये निर्देश लागू होते हैं, उनके अवलोकन से पता चलता है कि आयोग या बोर्ड से ऐसी सिफारिश प्राप्त होने के 6 महीने के भीतर ऐसी रिक्तियों को आयोग या बोर्ड द्वारा विभाग को भेजी गई सूचियों से भरा जा सकता है।यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है।ये निर्देश यह नहीं बताते हैं कि बोर्ड द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची केवल 6 महीने की अवधि के लिए मान्य है।नतीजतन, विवाद को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(7) श्री सूद ने यह भी तर्क दिया है कि एक चयनित व्यक्ति को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आम तौर पर, एक व्यक्ति जो किसी पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया है, उसे नियुक्त किया जाना चाहिए जब तक कि संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करने में अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के लिए कुछ कारण नहीं दिखाए जाते हैं। वर्तमान मामले में, लिखित बयान में किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है, जिसके कारण चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं दिया गया था। मेरे विचार में, प्राधिकरण को अपनी मर्जी से नियुक्ति से इनकार करने का आत्यन्तिक या मनमाना अधिकार नहीं है। एक उम्मीदवार जिसने पद के लिए प्रतिस्पर्धा की है और उपयुक्त पाया गया है, वह एक उचित उम्मीद का हकदार है कि उसे नियुक्त किया जाएगा। इस आशा को केवल एक वैध कारण से ही विफल किया जा सकता है।वर्तमान मामले में कोई वैध कारण नहीं दिखाए जाने के कारण, मुझे प्रतिवादी की ओर से उठाई गई आपत्ति में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

(8) तदनुसार, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता अपनी लागतों के भी हकदार होंगे जिनका आकलन रु 2,000 लगाया गया है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा